





सतपुड़ा टाइगर रिजर्व वाले जंगल में शाह ने दी थी पार्टी

# पूछताछ तक ही सीमित है पूर्व वन मंत्री शाह की चिकन पार्टी की जांच

भोपाल, दोपहर मेट्रो

पूर्व वन मंत्री एवं भाजपा विधायक विजय शाह की चिकन पार्टी वाली जांच केवल पूछताछ तक सिमटकर रह गई है। अधिकारी इससे आगे की कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं। पूछताछ के नाम पर केवल 5 से 6 वन कर्मियों को ही बार-बार परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मामले की जांच को जिस हिसाब से किया जा रहा है, उससे कई तरह के सबूत के मिटने की आशंका बढ़ गई है। पूरे मामले में बड़े अधिकारी हाथ डालने से बच रहे हैं। केवल जांच के नाम पर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर संदीप फैलोज को उलझा दिया है, जिनके अधिकार क्षेत्र में जांच आती ही नहीं है। सबसे पहले 19 दिसंबर को यह मामला सामने आया था तब से लेकर आज 22 दिसंबर है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर रिजर्व प्रबंधन व मप्र वन विभाग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है।



## कार्रवाई इसलिए नहीं

वन्यप्राणी मामलों के जानकारों का कहना है कि यही चिकन पार्टी किसी आम कर्मचारी या नागरिक ने की होती तो रिजर्व प्रबंधन से लेकर मप्र शासन कड़ी कार्रवाई कर देता लेकिन पार्टी पूर्व वन मंत्री एवं भाजपा के कदुदावर नेता विजय शाह के नेतृत्व में हो रही है इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि विभागीय मंत्री रह चुके शाह को यह शोभा नहीं देता, तब भी बाघ मूवमेंट वाले इलाके में इस तरह पार्टी की और खुद ही वीडियो भी बनाया, यह अपराध की श्रेणी में आता है। इस संबंध में कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसमें कोई दिवाइ नहीं दी जानी चाहिए।

## पीसीसीएफ पत्र लिखकर चुप बैठे

मामले की शिकायत जैसे ही पीसीसीएफ वन्यप्राणी कार्यालय पहुंची, उन्होंने दूसरे ही दिन फील्ड डायरेक्टर एल कृष्ण मूर्ति को पत्र लिखा और उसके बाद से चुप बैठे हुए हैं तो वहीं फील्ड डायरेक्टर पर गंभीर आरोप है कि उन्हीं के संरक्षण में चिकन पार्टी हुई है, मामला पूर्व मंत्री से जुड़ा है जो कि पूर्व में विभाग के ही मंत्री रह चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्व मंत्री किसी निचले अधिकारी से इंतजाम के लिए कहेंगे ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण से ही पार्टी का इंतजाम हुआ है।

# केंद्र के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल मप्र नया टीकाकरण अभियान: धूम्रपान करने वालों को भी लगेगा डोज

भोपाल, दोपहर मेट्रो

18 वर्ष से अधिक आयु वालों को भी टीबी की बीमारी से बचाने के लिए टीका लगाने का अभियान शुरू हो रहा है। इसमें अभी गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों के अलावा धूम्रपान

करने वालों को शामिल किया जा रहा है। भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश को भी चुना है। 26 जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका की एक डोज लगाई जाएगी। अभी जिलों का चयन होना बाकी है।

## शहरी बेघरों का होगा हेल्थ चेकअप

वहीं मप्र सरकार ने शहरी बेघरों के लिए संचालित आश्रय स्थलों में ठहरने वाले हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने की तैयारी की है। विभिन्न जिलों में नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय अंतर्गत 61 नगरीय निकायों में कुल 125 आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई ने कहा है कि आश्रय स्थलों में ठहरने वाले हितग्राहियों के स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने और बेघर व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं नगरीय निकायों के मैदान अमले को बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आश्रय स्थलों की मैपिंग उनके समीप संचालित सजीवनी क्लीनिक, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि से की गई है। आश्रय स्थल प्रभारी समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं मेप की गई संस्था के प्रभारी अधिकारी से समन्वय कर आश्रय स्थलों में ठहरने वाले हितग्राहियों के स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने की कार्ययोजना तैयार करेंगे। आश्रय स्थलों के निरीक्षण हेतु एक दल का गठन किया जाएगा। दल प्रत्येक 15 दिवस में निरीक्षण करेगा। निकाय शीत ऋतु में मोबाइल वैन के माध्यम से रात्रि के समय फेरे लगाकर बेघरों को सुविधाजनक तरीके से आश्रय स्थल तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।



बताया जाता है कि यह टीकाकरण शुरू करने की तारीख भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। अभी सिर्फ बच्चों को ही टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। धूम्रपान करने वालों को पहचान के लिए सर्वे कराया जाएगा। राज्य टीकाकरण अधिकारी डा. संतोष शुक्ला ने बताया कि केंद्र ने पहले मात्र मध्य प्रदेश को ही पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना था, पर अब लगभग 15 राज्य शामिल हो चुके हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बताने के लिए एक कार्यशाला भी हो चुकी है। डा. शुक्ला ने बताया कि दाहिने हाथ में 0.1 मिली टीका लगाया जाएगा। टीका उन्हें लगेगा जिनकी प्रतिरोधक क्षमता किन्हीं कारण से कम हो जाती है। बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होने पर सबसे पहले टीबी जकड़ती है। एड्स से पीड़ित रोगियों को भी सबसे पहले टीबी होती है।

## रात्रिभोज पर चर्चा...



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मप्र के सांसदों से बीती रात दिल्ली में से रात्रिभोज पर प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

## भाजपा विधायक कश्यप इस बार भी नहीं लेंगे वेतन भत्ते

भोपाल, दोपहर मेट्रो। रतलाम शहर से भाजपा विधायक चेतन्य कुमार कश्यप इस बार भी विधायक के रूप में मिलने वाले वेतन-भत्ते नहीं लेंगे। इसकी घोषणा उन्होंने की है। कश्यप ने कहा कि राष्ट्रसेवा और जनहित मेरा ध्येय है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं जन सेवा में थोड़ा सा योगदान कर सकूँ। इसी तारतम्य में मैंने विधायक के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन नहीं लेने का निश्चय किया है। पिछली दो विधानसभा में भी मैंने वेतन भत्ते ग्रहण नहीं किए थे। वहीं कल जब विस में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने छिंदवाड़ा से विधायक कमल नाथ के सत्र से अनुपस्थित रहने को अनुमति पर सदन की सहमति की सूचना पढ़ी। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस सदन में नहीं आने लायक तो उनको इनकी पार्टी ने ही बनाया है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी हटा दिया, अब वे किस मुह से यहाँ पर आएँ। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार कहा ने कि शायद कैलाश को पता नहीं है, उनके यहां परिवार में गमी हो गई है, इस कारण वे नहीं आ पाए।

## मेट्रो एंकर

## मुख्य न्यायाधीश ने किया शुभारंभ

# हाइकोर्ट में एकीकृत वीडियो निगरानी प्रणाली, ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम शुरू

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि मल्लिमथ ने मप्र हाई कोर्ट में आम नागरिकों की सहूलियत के लिये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी व्यवस्थाओं का शुभारंभ किया है। उच्च न्यायालय जबलपुर में वीडियो निगरानी प्रणाली और कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम-क्लास परियोजनाएं प्रारंभ हो गई हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय, जबलपुर के अधिकारी उपस्थित थे।

यह देश में पहली बार है, जब किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में सभी जिला और तहसील अदालतों के लिए कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षित अदालत परिसरों की ओर बढ़ते हुए, हाईकोर्ट ने एकीकृत वीडियो निगरानी प्रणाली (आईवीएसएस) और कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (क्लास) शुरू की है।



## आईवीएसएस और क्लास क्या है?

1. एकीकृत वीडियो प्रबंधन प्रणाली।
2. कोर्ट रूम ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम।
3. संग्रह और लाइव के साथ-साथ ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग सेट-अप।
4. जबलपुर में डेटा सेंटर एवं कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना।

## 210 कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग

यह अपने आप में देश की एक अग्रणी परियोजना है जो पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को अपनाती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिम्मेदार नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अन्य अदालतों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में एक अग्रणी तकनीकी परियोजना है जो हाई कोर्ट द्वारा प्रशासित अदालत परिसर को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी। नई प्रौद्योगिकी को अपनाने और उनका एकीकरण मध्य प्रदेश न्यायपालिका को डिजिटल युग के लिए तैयार करेगा। अदालत परिसर में न्याय की यात्रा सभी संबंधित पक्षों - न्यायाधीशों, वकीलों और अधिवक्ताओं, अदालत के कर्मचारियों, पुलिस जैसी सुरक्षा एजेंसियों और बड़े पैमाने पर जनता के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। अदालत परिसरों में व्यवधान की कई घटनाएं हुई हैं। अदालत परिसरों को सुरक्षित बनाने के लिए सिस्टम तेनात करना और तंत्र स्थापित करना महत्वपूर्ण कदम है।

## समन्वय बैठक का आयोजन



मध्य प्रदेश समाज सेवा संस्था के द्वारा लोक आघारित विकास प्रक्रिया के अन्तर्गत एम.पी.एस.एस.एस.कार्यालय के सभागार में समाज सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की समन्वय बैठक का आयोजन हर्बल औषधि, पोषण, भूखमरी और कुपोषण के विषय पर किया गया।

# आठ नवागत आईएस अफसरों का तबादला

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मप्र की यादव सरकार ने आठ सहायक कलेक्टरों का तबादला किया है। 2021 बैच के इन आइएएस अधिकारियों को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बनाया गया है। इसमें अर्थ जैन को मंडला से उज्जैन, वैशाली जैन को छिंदवाड़ा से हुजूर रीवा, दिव्यांशु चौधरी को बैतूल से डबरा ग्वालियर, सृजन वर्मा को नीमच से सिंगरौली, अर्चना कुमारी को विदिशा से सीहोरा जबलपुर, अरविंद कुमार शाह को शिवपुरी से शहडोल, शिवम प्रजापति को धार से पुनासा खंडवा और टी प्रतीकराव को देवास से इटारसी नर्मदापुरम पदस्थ किया है।

उधर दो दिन पहले हुए आदेश के मुताबिक अब जनसंपर्क विभाग के सचिव विवेक पोरवाल ने आयुक्त व एमडी माध्यम का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। पोरवाल ने जनसंपर्क की कार्यप्रणाली की वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करते हुए बेहतर तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।



## शिकायतों के चलते गुप्ता हटे, वरिष्ठ भी

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी के बाद अब उप सचिव नीरज कुमार वरिष्ठ की छुट्टी हो गई। अभी उन्हें मंत्रालय में उप सचिव पदस्थ किया है। अभी रस्तोगी को भी कोई दायित्व नहीं दिया गया है। वरिष्ठ ने लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ काम किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को दो वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों पदस्थापनाएं की हैं। इनमें आयुक्त व संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मुकेश चंद्र गुप्ता को भी इस दायित्व से मुक्त कर दिया। वे अब प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी रहेंगे। इंदौर में पदस्थ श्रम आयुक्त श्रीकांत बनोट को वर्तमान दायित्व के साथ आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

# दोपहर मेट्रो

अपने कारोबार-उत्पाद को आगे बढ़ाएं दोपहर मेट्रो के साथ



विज्ञापनों के लिए संपर्क करें

प्रधान कार्यालय 182 - ए शाहपुरा (मनीषा मार्केट के पास) भोपाल

फोन नं. - 0755-4917524, 0755-2972022

## संपादकीय

## सुधार का सिलसिला व सदी

में तो बदलाव किया ही, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग की प्रक्रिया में भी पूर्ण सुधार किया। राइट्स ऑफ वे की प्रक्रिया भी आसान बनाई गई और वाजिब शुल्क निर्धारित किए गए। यही नहीं सुरक्षा उपायों के साथ सौ फीसदी एफडीआई की भी इजाजत दी गई है। वहीं टूजी एलोकेशन को लेकर हुए विवाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे अवैध करार दिए जाने के बाद इस क्षेत्र में जो शिथिलता दिखने लगी थी, वह इन सुधारों से दूर हुई। इसका असर भी इंडस्ट्री पर दिखा। बेस ट्रांससीवर स्टेशन की संख्या इस दौरान 6.25 लाख से बढ़कर 25.5 लाख हो गई। ब्रॉडबैंड इंटरनेट के उपभोक्ता 1.5 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ हो गए। मंजूरी में लगने वाला औसत

समय 230 दिनों से घटकर 10 दिन हो गया। परिणाम यह कि 3 लाख करोड़ के अधिक एजीआर के साथ टेलिकॉम अब एक सनराइज सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है। टेलिकॉम सुधारों की कड़ी को आगे बढ़ा रहा है। स्पेक्ट्रम सौंपने का मुख्य तरीका ऑक्शन होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट केवल जनहित (जैसे मेट्रो, सामुदायिक रेडियो) सरकारी कार्य (जैसे रक्षा, रेलवे, पुलिस) और उन क्षेत्रों तक सीमित होगा, जिनमें तकनीकी या आर्थिक कारणों से ऑक्शन को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। इसमें काम में न लाए जाने वाले स्पेक्ट्रम सरकार को वापस लौटाने का भी प्रावधान है। भूलवश कानून का उल्लंघन होने पर स्वेच्छ से अपनी गलती मानने का

विकल्प है। विवाद निपटाने के लिए भी बहुस्तरीय व्यवस्था है और इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इंटरसेशन के कुछ अधिकार सरकार के पास होने जरूरी है। फिर भी कुछ हलकों में इससे जुड़े पहलुओं पर चिंता है मगर चिंता का औचित्य और उसका हल सही अर्थों में तभी सामने आएगा जब यह बिल कानून बनेगा और इसके उपयोग या दुरुपयोग से जुड़े पहलु व्यवहार में दिखने शुरू होंगे। इसमें प्रावधान हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी आपात स्थिति में सरकार टेलिकॉम सेवा तथा मोबाइल नेटवर्क को अस्थाई तौर पर अपने नियंत्रण में ले सकती है। वैसे देखा जाए तो यह बहुत सुधारवादी कदम साबित हो सकता है, जिसकी उम्मीद कई साल से की जा रही थी। अब आने वाले समय में इसका क्रियान्वयन बहुत महत्वपूर्ण होगा। उल्लेखनीय होगा कि केंद्र सरकार ने अब 138 साल पुराने टेलीग्राफ एक्ट को बदलने की पहल की है।



## सुविचार

काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हारने के लिए, कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े।

- अज्ञात



**लो** कसभा में पेश टेलिकॉम सुधार बिल में जिन कदमों का प्रस्ताव किया गया है, उससे टेलिकॉम इंडस्ट्री और डिजिटल इकॉनमी को और रफ्तार मिल सकती है। दरअसल लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम एलोकेशन सहित इस सेक्टर के रेग्युलेटरी मैकेनिज्म में बड़े बदलावों का प्रस्ताव किया गया है। यह बिल कानून बन जाने के बाद इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स (अनलॉकड पजेशन) एक्ट 1950 जैसे कानूनों की जगह लेगा। ये कानून तेजी से बदलते इस क्षेत्र के लिए पुराने पड़ते जा रहे थे और इन्हें बदलने की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। इस बिल में प्रस्तावित बदलावों पर विचार करने से पहले पिछले दस वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में हुए सुधारों और उनके परिणामों पर एक नजर डाल लेना बेहतर होगा। सरकार ने इस दौरान एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की परिभाषा, बैंक गारंटी की जरूरत

## निशाना

## गिरी आखिर गाज !



- कृष्णराज

हुई कार्रवाई अब । गिरी आखिर गाज । गैरजिम्मेदार वो । सर पर जिनके ताज । हुई हरकत इस तरह । है शर्मिंदा देश । कार्यशैली ऐसी है । दर्जा जिन्हें विशेष । धीरे-धीरे परतें । लगीं खुलने आज । है सब कुछ स्पष्ट । ना रहा कुछ स्पष्ट । है पड़ता भुगतना । किए जो भी काम । प्राप्त कर लिया देश । लेकिन कुछ पैगाम ।

## आज का इतिहास

- 2010 - अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिकता से जुड़े कानून पर दस्तखत कर सेना में समलैंगिकों के लिए रास्ता साफ कर दिया।
- 2008 - सशक्त बलों के वेतन में विसंगतियों के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- 2007 - फ्रेंच गुआना के गौस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किये गए यूरोप के एरियन रॉकेट ने अंतरिक्ष कक्षा में दो उपग्रह स्थापित किये।
- 2006 - भारत और पाकिस्तान ने स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया।
- 2005 - ईरान ने ज़हरीली गैस से हजारों ईरानियों को मारने के आरोप पर सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाने की मांग की।
- 2002 - दवाओं के दुरुपयोग के मसले पर दक्षे देशों के स्वयंसेवी संगठनों की तीन दिवसीय बैठक काठमांडू में शुरू।
- 1989 - रोमानिया के राष्ट्रपति चाऊश्केस्क्यू का तख्ता पलटा तथा वे देश छोड़कर भागते समय गिरफ्तार।
- 1978 - थाईलैंड ने सविधान अंगीकार किया।
- 1975 - दो आँखें बारह हाथ, झनक-झनक पायल बाजे, गुंज उठी शहनाई, संपूर्ण रामायण, गुड्डि और आशीर्वाद जैसी फिल्मों में संगीत देने वाले वसंत देसाई का निधन हुआ।
- 1971 - तत्कालीन सोवियत संघ ने जमीन के नीचे परमाणु परीक्षण किया।
- 1966 - जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.), नई दिल्ली की स्थापना जेएनयू अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय संसद द्वारा की गई थी।
- 1961 - अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
- 1957 - ओहायो के कोलंबो चिड़िया घर में कोलो नामक गुरिल्ला के बच्चे का जन्म हुआ जो चिड़िया घर में पैदा होने वाला पहला गुरिल्ला था।
- 1947 - इटली की संसद ने नया संविधान अंगीकार किया।
- 1941 - यूगोस्लाविया में मार्शल टिटो ने सेना की नई ब्रिगेड का गठन किया।

## ज्ञानेंद्र रावत

**पि** छले दिनों दुबई में लगभग दो सप्ताह चले दुनिया के तकरीबन 200 देशों के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज-28 के आयोजन के पीछे भी यही आकांक्षा थी कि इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने और भविष्य में उससे मिलने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाये। दरअसल, वर्ष 2015 के पेरिस समझौते का मुख्य मकसद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को इस हद तक कम करना था ताकि वैश्विक तापमान में वृद्धि औद्योगिक काल से पूर्व के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होने पाये। हकीकत यह रही कि इस दिशा में जो भी प्रयास किये गये वे ऊंट के मुंह में जिरा ही साबित हुए। सबसे बड़ी बात इस हेतु जो संरचनात्मक ढांचे की जरूरत थी, वे निर्मित ही नहीं किये गये। दरअसल इनके बारे में सोचा ही नहीं गया। फिर जिस सामाजिक भागीदारी की बेहद जरूरत थी, उसकी तो कल्पना ही नहीं की गयी। जबकि वैश्विक स्तर पर ऐसी चुनौतियों से निपटना सामाजिक भागीदारी के बिना असंभव है। उम्मीद थी कि कॉप-28 में इस दिशा में मंथन होगा।

गौरतलब है कि दुबई में जलवायु सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों का बुरी तरह से सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन से दुनिया को होने वाला नुकसान साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है। इससे हर साल दुनिया को अरबों डॉलर की चपत लग रही है। हकीकत में दुनिया की जीडीपी को 1.8 फीसदी का नुकसान हो रहा है जो करीब 1.5 खरब डॉलर के बराबर है। वहीं भारत को करीब 8 फीसदी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्ष 2022 में भारत को करीब 30 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। लगातार गर्म होती दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है सूखा। भारत सहित दुनिया के 23 देश गंभीर सूखे की मार झेल रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से पर्वतीय देशों के

## कॉप-28 जलवायु सम्मेलन

## दुनिया बचाने के आधे-अधूरे प्रयास



लिए खतरा बढ़ रहा है। उसे देखते हुए 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में तीन डिग्री की बढ़ोतरी होती है तो उस स्थिति में खाड़ी देश रहने काबिल नहीं रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कोई अछूता नहीं है। इसका प्रभाव गरीबों पर ही नहीं,

इंसान के मस्तिष्क और हृदय पर भी घातक प्रभाव पड़ रहा है। यहां तक जानवर भी इसके दुष्प्रभाव से अछूते नहीं रहे हैं। इस सम्मेलन में पहली बार जलवायु परिवर्तन के संकट की व्यापकता और इस बारे में तत्काल

कार्रवाई की जरूरत महसूस की गयी। इस सत्य को स्वीकार भी किया गया कि संकट के समाधान हेतु हमें आपस में न केवल सहयोग करना होगा बल्कि साथ-साथ इसका मुकाबला करना होगा। बावजूद इसके कि संपन्न और वंचित देशों के बीच विभाजन की खाई पहले की तरह बरकरार बनी रही। जलवायु परिवर्तन की समस्या के मुकाबले के लिए सबसे बड़ी जरूरत पूंजी की है, कोष की है। यह मामला बरसों से विकसित देशों की इस बाबत आनाकानी के चलते उलझा हुआ है। सम्मेलन के अंतिम दिन जो सहमति बनी उसके अनुसार, सभी देश जीवाश्म ईंधन की जगह स्वच्छ ऊर्जा की ओर रुख करें। फिर भी वर्ष 2050 तक नेट जीरो तक पहुंचने, हरित ऊर्जा को साल 2030 तक तीन गुना तथा ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने, ट्रांसिशन पयूल का जिक्र करने, देशों को अपने स्वेच्छिक जलवायु लक्ष्य 2024 तक पूरे करने और अमीर देशों द्वारा अपने जंगलों को कार्बन ऑफसेट के रूप में उपयोग करने के लिए गरीब देशों को भुगतान करने की बात सम्मेलन में हुई। यदि इसको सम्मेलन की सफलता बनाया जा रहा है तो इसे उपलब्धि तो नहीं माना जा सकता।

सवाल यह है कि कार्बन कैप्चर तकनीक के जरिये नेट जीरो की राह बेहद खर्चीली है। इस तकनीक से 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए दुनिया को 30 खरब डॉलर की राशि अधिक खर्च करनी पड़ेगी। विशेषज्ञों की नजर में इस तकनीक पर निर्भर रहना उचित नहीं है क्योंकि इससे सरकारी खुद को प्रतिस्पर्धी नुकसान की स्थिति

में डाल लेंगे। सबसे बड़ी विफलता यह ही है कि सम्मेलन में गरीब और विकासशील देशों को जलवायु लक्ष्य हासिल करने के लिए धन की आवश्यकता कैसे पूरी होगी। साथ ही ऐतिहासिक प्रदूषकों की जवाबदेही क्या और कैसे तय होगी, ग्लोबल साउथ के लिए जलवायु लचीलापन और कम कार्बन उत्सर्जन को दिशा में बदलाव के वित्त पोषण के लिए प्रभावी तंत्र कैसे बनेगा। इस पर और जीवाश्म ईंधन के उत्पादन और खपत की कटौती के मामले में कोई खुलासा न होना संदेह उत्पन्न करता है। फिर वित्त के मामले पर स्पष्टीकरण का अभाव और मोथेन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य निर्धारण न होना और अनुकूलन प्रयासों में तेजी लाने के प्रयासों के लक्ष्य का घोषित न किया जाना, पेरिस समझौते के अक्षरशः पालन के सवाल पर चुपकी सम्मेलन की सफलता के दावे पर सवालिया निशान लगाते हैं। हमें यह समझ लेना होगा कि चुनौती बहुत बड़ी है। केवल प्रस्तावों से कुछ नहीं होने वाला। वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार घरेलू कार्यों, परिवहन और बिजली उत्पादन आदि के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग का सवाल जटिल है। इस पर अंकुश बेहद जरूरी है। लेकिन 2050 तक जलवायु संकट के प्रमुख कारक जीवाश्म ईंधन न्यायसंगत तरीके से खत्म किये जाने पर सहमति एक अच्छा संकेत तो है लेकिन इसके लिए 27 वर्ष का समय देना न्यायोचित नहीं है। उस स्थिति में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में त्वरित कटौती की बात और स्वच्छ दुनिया की उम्मीद करना बेमानी है।

साभार : यह लेखक के अपने विचार हैं।









## खरीददारी कर घर लौट रहे बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत

गोलखेड़ी टोलटैक्स के पास ईटखेड़ी में हुआ हादसा

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

खरीददारी करके भोपाल से नजीराबाद लौट रहे बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। एंबुलेंस की मदद से गंभीर हालत में उसे अस्पताल रवाना किया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद अज्ञात आरोपी चालक अपना वाहन लेकर घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस ने फिलहाल मर्मा कायम कर अज्ञात आरोपी चालक और वाहन की तलाश शुरू कर दी है। वाहन की

तलाश के लिए घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ग्राम गढ़ाखुर्द नजीराबाद निवासी राजेश प्रजापति पुत्र बटनलाल प्रजापति (30) एमपी ऑनलाइन शॉप पर कप्टर ऑपरेटर था। बुधवार देर शाम वह भोपाल से खरीददारी कर अपने गांव लौट रहा था। इस बीच शाम करीब पाँच बजे किसी अज्ञात वाहन ने राजेश की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी चालक वहाँ

रुका नहीं बल्कि अपना वाहन लेकर फरार हो गया। घटना के बाद वहाँ से गुजर रहे लोगों ने गंभीर रूप से घायल राजेश को अस्पताल रवाना किया था। लेकिन उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक राजेश प्रजापति की करीब पाँच साल पहले शादी हुई थी। उसका एक तीन साल का बेटा व एक साल की बेटी है। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था। आरोपी चालक व वाहन की सरगमी से तलाश की जा रही है।

## मिनी ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत, दूसरा गंभीर

सूखी सेवनिया पुलिस के मुताबिक न्यू राजीव नगर सेमरा निवासी वृंदावन लोधी (40) प्राइवेट काम करता था। बुधवार को वह अपने एक साथी के साथ सूखी सेवनिया गया हुआ था। बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे सूखी सेवनिया से भोपाल आते समय इंडियन पेट्रोल पंप के पास चौपड़ा कला इलाके में अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक वाहन लेकर फरार हो गया। स्थानीय रहवासियों ने एंबुलेंस की मदद से वृंदावन और उसके साथी को हमीदिया अस्पताल रवाना किया, जहाँ वृंदावन लोधी की मौत हो गई जबकि उसके साथी की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रधान आरक्षक मुकेश कटियार ने बताया कि मृतक के पास मिले की-पेड मोबाइल में मिले नंबरों पर संपर्क करने पर परिजनों से बात हुई थी। उसके बाद ही पहचान हो सकी। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी मिनीट्रक (407 वाहन) ने टक्कर मारी है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चैक कर वाहन और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।



## पानी गर्म करने वाली रॉड से पत्नी को जलाया, पुलिस ने दर्ज किया केस



भोपाल, दोपहर मेट्रो

कमला नगर इलाके में पति ने पत्नी को पानी गर्म करने वाली रॉड (इमर्सन रॉड) से जला दिया। इससे उसका हाथ जल गया। इतना ही नहीं आरोपी के मारपीट से महिला को चोट लगी है। कमला नगर पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, नेहरू नगर निवासी 30 वर्षीय सुरभि सिंह ठाकुर की इसी साल मार्च में अजीत सिंह ठाकुर से शादी हुई है। सुरभि गृहणी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही पति शराब के नशे में घर आता है। मारपीट करता है। बुधवार शाम करीब 4 बजे पति नशे की हालत में घर पहुंचा। घर आते ही उसके साथ गाली-गालौच करते हुए मारपीट कर दी। इसी बीच पानी गर्म करने वाली रॉड से उसके दाहिने हाथ को जला दिया। सुरभि के गले में मारपीट से चोट आई है। सुरभि ने घटना की जानकारी अपने पिता ऋषि जौहरी को दी। थोड़ी देर बाद उसके पिता पहुंचे। उन्होंने दामाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। वह ससुर के साथ भी गाली-गालौच करने लगा। पत्नी को उसने धमकी दी कि यदि थाने रिपोर्ट करने गई तो जान से खत्म कर दूँगे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

## मामूली बात पर कहासुनी, भाई ने बहन पर गर्म चाय फेंकी

भोपाल, दोपहर मेट्रो

अवधपुरी थाना क्षेत्र स्थित शिवलोक फेस टू में बहन भाई के बीच हुई मामूली कहासुनी के बाद बड़े भाई ने छोटी बहन पर गर्म चाय फेंक दी। चाय शरीर पर गिरने के कारण बहन झुलस गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रीति समोलिया पिता सुरेश समोलिया (19) शिवलोक फेस टू, अवधपुरी में रहती है। उसने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि उसका बड़ा भाई शांतनु उससे आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद करता है। कल गुरुवार सुबह भी शांतनु से उसकी कहासुनी हुई थी। कहासुनी बढ़ने पर शांतनु ने प्रीति पर गर्म चाय फेंक दी।

## पुलिसकर्मियों के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन

भोपाल, दोपहर मेट्रो

पुलिसकर्मियों के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर समय-समय पर कार्यशाला एवं स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में आरंभ संस्था

द्वारा गुरुवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में पुलिसकर्मियों के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पुलिस आयुक्त कार्यालय एवं रक्षित केंद्र के 110 पुलिसकर्मियों का नेत्र परीक्षण किया गया। आरंभ

संस्था द्वारा 50 पुलिसकर्मियों को चश्मे भी वितरित किए गए, जबकि शेष पुलिस कर्मचारियों को बाद में चश्मे वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने भी नेत्र परीक्षण कराया और शिविर के लिए आरंभ संस्था का आभार माना।

## मेट्रो एंकर

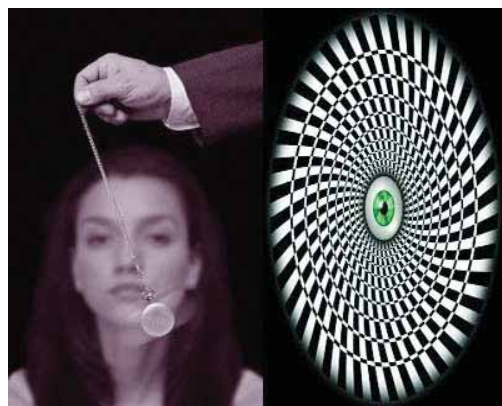
## सीसीटीवी फुटेज से पुलिस कर रही पहचान

# सम्मोहन क्रिया से महिला के कान के टॉप्स टगने वाले जालसाजों का नहीं लगा सुराग

भोपाल, दोपहर मेट्रो

कटारा हिल्स थाना क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी लहारपुर में बुटिक का संचालन करने वाली महिला को सम्मोहन क्रिया से टगने वाले जालसाजों का सुराग नहीं लग सका है। पुलिस ठगों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी फुटेज वायरल किए हैं, लेकिन दो महीने बीत जाने पर भी ठगों का सुराग नहीं लगा है।

पुलिस के अनुसार ज्योति शर्मा पति प्रकाश नारायण शर्मा (50) एलआईजी फर्स्ट, 204, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, लहारपुर में रहती हैं और कटारा स्कूल के पास बुटिक का संचालन करती हैं। गत 4 अक्टूबर 2023 को दोपहर करीब करीब साढ़े 12 बजे वह दुकान पर थी। इस



दौरान एक बाइक पर दो युवक पहुंचे। एक युवक उनके पास पहुंचा और दूसरा बाइक के पास खड़ा रहा। उनके पास पहुंचे युवक ने उनसे सफेद रंग का ब्लाउज पीस मांगा। ज्योति ने ब्लाउज पीस दिखाया

और उसने एक पीस पसंद कर पांच सौ रुपये का नोट थमा दिया। ज्योति ने उसे ब्लाउज पीस के साथ

चार सौ रुपये लौटाए थे, तभी उसने कोई मंत्र पढ़ा और कहा कि अपने कान के टॉप्स दे दो। ज्योति ने उसके कहने पर कान के टॉप्स उतारकर दे दिए। कान के टॉप्स हाथ लगने के बाद आरोपी बाइक के पास खड़े अपने साथी के साथ चला गया। कुछ देर बाद

ज्योति को पता चला कि उनके कान के टॉप्स युवक लेकर गया है तो उन्होंने अपनी बेटी को आवाज दी। मां बेटी बाहर निकली तो बाइक सवार दोनों आरोपी बरखेड़ा पठानी की तरफ भाग निकले थे।

## युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

गोविंदपुरा थाना क्षेत्र स्थित बरखेड़ा पठानी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कल सुबह चार बजे अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे एम्स लेकर पहुंचे थे। एम्स में डॉक्टर ने चेक करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अनुमान है कि उसे हार्ट अटैक आया है। दरअसल, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में भी हार्ट अटैक की बात सामने आई है। पुलिस फुल पीएम रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रही है। एएसआई वासुदेव सविता ने बताया कि सत्री चौकसे पित स्वर्गीय ओम प्रकाश चौकसे (32) बरखेड़ा पठानी में रहता था। उसका मकान मुख्य सड़क पर है और वह मकान में ही सामने पंचर की दुकान का संचालन करता था। परिजन ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब चार बजे सत्री की तबीयत बिगड़ी थी। उसे तत्काल एम्स लेकर पहुंचे, वहाँ एक घंटे बाद करीब पांच बजे डॉक्टर ने सत्री को मृत घोषित कर दिया।



## हमीदिया परिसर स्थित रैन बसेरा में जीवन गुजार रहे रंगकर्मी की बीमारी के चलते मौत

हमीदिया अस्पताल परिसर स्थित रैन बसेरा में जीवन गुजार रहे एक रंगकर्मी की बीमारी के चलते मौत हो गई। यहाँ रहने वाले दो अन्य अज्ञात लोगों की भी बीमारी के कारण मौत हो गई। पुलिस ने सभी मामलों में मर्मा कायम कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह सूचना मिली कि रैन बसेरा में रहने वाले 35 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की बीमारी से मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मृतक की तलाशी ली तो उसकी जेब में पर्ची में लिखा एक मोबाइल नंबर मिला। संपर्क करने पर मृतक का नाम अपूर्व शुक्ला पता चला और मोबाइल नंबर उसकी मौसी का था। अपूर्व एक रंगकर्मी था और वह पत्रकारिता तथा फोटोग्राफी भी करता था। उसके पिता पंकज शुक्ला सीनियर अधिवक्ता और पत्रकार रह चुके हैं। वह पहले जहांगीराबाद में रहता था, लेकिन बाद में अलग-अलग स्थानों पर रहने लगा था। उसकी मौसी ने अपने साथ कटनी में रहने का बोला था, लेकिन अपूर्व उनके साथ नहीं गया। पिता के निधन के बाद से वह लगातार डिप्रेशन में चला गया और बाद में रैन बसेरा में अपना टिकाना बना लिया था। यहाँ पर 45 साल और 60 साल के दो अन्य लोगों की भी बीमारी के चलते मौत हो गई है। उनके परिजनों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

